COHERENCE – The Multidisciplinary Research Journal
Volume No: 15, Issue No: 2, Year: 2024 (July-December)
PP: 16-23
ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

ग्रामीण बिहार में गरीबी उन्मूलन की दिशा में विश्व बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रमों की भूमिका: उपलब्धियाँ, सीमाएँ और चुनौतियाँ

मितु कुमारी
विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश

ग्रामीण बिहार में गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय पहुँच, आजीविका-सुरक्षा, सामाजिक भागीदारी और बुनियादी सुविधाओं की सम्मिलित वंचना के रूप में दिखाई देती है। इस संदर्भ में विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे "जीविका" के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण निर्धन परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक संस्थाओं, बैंक-लिंकेज, आजीविका प्रशिक्षण और सामाजिक सशक्तीकरण से जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और इसमें विश्व बैंक, नीति आयोग, यूएनडीपी, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी तथा प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययनों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, किंतु गरीबी का ग्रामीण चरित्र अब भी गहरा है। जीविका जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं की सामूहिकता, कम लागत वाले ऋण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक जागरूकता और आजीविका-विविधीकरण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। फिर भी आय-वृद्धि की स्थिरता, कौशल-आधारित उद्यमिता, बाजार-संपर्क, उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण और क्षेत्रीय असमानता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शोध-पत्र का निष्कर्ष है कि विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों को केवल ऋण-आधारित मॉडल तक सीमित न रखकर कृषि-प्रसंस्करण, स्थानीय उद्यम, डिजिटल वित्त, महिला उत्पादक समूह और पंचायत-स्तरीय गरीबी मानचित्रण से जोड़ना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण बिहार, विश्व बैंक, जीविका, गरीबी उन्मूलन, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय समावेशन, बहुआयामी गरीबी

1. प्रस्तावना

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से कृषि-प्रधान, श्रम-आधारित और निम्न आय-संरचना वाली रही है। राज्य की बड़ी आबादी गाँवों में निवास करती है; नीति आयोग के बिहार संबंधी व्यापक आर्थिक दस्तावेज के अनुसार 2023 तक बिहार की लगभग 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, जबकि 2022–23 में राज्य के 49.6% श्रमिक कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े थे [1]। यह संरचना बताती है कि बिहार में गरीबी उन्मूलन की कोई भी गंभीर रणनीति ग्रामीण आजीविका, कृषि-आधारित रोजगार, महिला श्रम-भागीदारी, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक संस्थाओं को केंद्र में रखे बिना प्रभावी नहीं हो सकती।

विश्व बैंक ने बिहार में गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रत्यक्ष रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, अर्थात जीविका, के माध्यम से निभाई। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अनुसार यह परियोजना बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से संचालित की गई [2]। विश्व बैंक ने जीविका और बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कुल 453 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईडीए ऋण सहयोग का उल्लेख किया है तथा बिहार सरकार ने भी 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिपक्षीय वित्तपोषण दिया [3]।

© Copyright @ Authors

भारत में बहुआयामी गरीबी में गिरावट का राष्ट्रीय परिदृश्य भी इस अध्ययन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। नीति आयोग से संबंधित 2024 के प्रेस सूचना ब्यूरो विवरण के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी अनुपात 2013–14 के 29.17% से घटकर 2022–23 में 11.28% रह गया, और इस अवधि में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए [4]। इसी स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, जो राज्य-स्तरीय गरीबी कमी की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य है [4]।

फिर भी बिहार की स्थिति को केवल उपलब्धियों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यूएनडीपी और नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबों का अनुपात 2015–16 में 51.89% था, जो 2019–21 में घटकर 33.76% हो गया; यह 18.13 प्रतिशत-बिंदु की गिरावट है, लेकिन इस कमी के बाद भी बिहार देश में उच्च गरीबी वाले राज्यों में रहा [5]। अतः यह शोध-पत्र यह प्रश्न उठाता है कि विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने ग्रामीण बिहार में गरीबी उन्मूलन में किस प्रकार योगदान दिया, उनकी उपलब्धियाँ क्या रहीं, उनकी सीमाएँ कहाँ रहीं और आगे की चुनौतियाँ क्या हैं।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

पहला, ग्रामीण बिहार में विश्व बैंक समर्थित गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों, विशेषतः जीविका, की संरचना और कार्य-प्रणाली का विश्लेषण करना।

दूसरा, बहुआयामी गरीबी, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तीकरण और आजीविका-विविधीकरण से जुड़े उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों की व्याख्या करना।

तीसरा, जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण ऋण, सामाजिक पूँजी और स्थानीय संस्थागत क्षमता के निर्माण का मूल्यांकन करना।

चौथा, कार्यक्रम की सीमाओं और क्रियान्वयन-स्तर की चुनौतियों की पहचान करना।

पाँचवाँ, ग्रामीण बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए नीति-आधारित सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-पद्धति एवं आँकड़ों के स्रोत

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें विश्व बैंक के परियोजना विवरण, विश्व बैंक परिणाम-रिपोर्ट, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी की संस्थागत जानकारी, नीति आयोग तथा यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक, प्रेस सूचना ब्यूरो के आधिकारिक विवरण और 3ie द्वारा प्रकाशित जीविका प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययन का उपयोग किया गया है। विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी, प्रतिशत परिवर्तन, सापेक्ष कमी, वार्षिक औसत कमी और तुलनात्मक तालिकाओं का उपयोग किया गया है। जहाँ प्रत्यक्ष परियोजना-स्तरीय सूक्ष्म आय-आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ उपलब्ध प्रभाव-मूल्यांकन निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक व्याख्यायित किया गया है।

4. ग्रामीण बिहार में गरीबी की पृष्ठभूमि

बिहार में गरीबी का स्वरूप आयगत और बहुआयामी दोनों है। बहुआयामी गरीबी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर की संयुक्त वंचनाओं को मापती है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 2015–16 में 32.59% से घटकर 2019–21 में 19.28% हुआ, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.65% से घटकर 5.27% हुआ [5]। इससे स्पष्ट है कि गरीबी में कमी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तीव्र रही, किंतु ग्रामीण गरीबी का स्तर अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

बिहार में स्थिति और अधिक जटिल रही है। राज्य में बहुआयामी गरीबी 2015–16 में 51.89% थी, जो 2019–21 में घटकर 33.76% हो गई [5]। यह कमी महत्त्वपूर्ण है, लेकिन 2019–21 में भी हर 100 व्यक्तियों में लगभग 34 व्यक्ति बहुआयामी गरीबी में थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, परंतु गरीबी का आधार अभी भी व्यापक है।

तालिका 1: बहुआयामी गरीबी में परिवर्तन

क्षेत्र/राज्य	**2015–16 में गरीबी अनुपात**	**2019–21 में गरीबी अनुपात**	**कमी**	**सापेक्ष कमी**
भारत ग्रामीण	32.59%	19.28%	13.31 प्रतिशत-बिंदु	40.84%
भारत शहरी	8.65%	5.27%	3.38 प्रतिशत-बिंदु	39.08%
बिहार	51.89%	33.76%	18.13 प्रतिशत-बिंदु	34.94%

बिहार में गरीबी अनुपात में 18.13 प्रतिशत-बिंदु की कमी हुई। सापेक्ष कमी की गणना इस प्रकार की गई है:

$$\frac{51.89 - 33.76}{51.89} \times 100 = 34.94\%$$

इसका अर्थ है कि 2015–16 की तुलना में 2019–21 तक बिहार के बहुआयामी गरीबी अनुपात में लगभग 35% की सापेक्ष कमी हुई। फिर भी अंतिम स्तर 33.76% होने के कारण राज्य की चुनौती राष्ट्रीय औसत से अधिक बनी रही।

5. विश्व बैंक समर्थित जीविका कार्यक्रम की संरचना

जीविका का मूल आधार यह था कि गरीबी से लड़ने के लिए गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को संगठित सामुदायिक संस्थाओं में जोड़ा जाए। 3ie के प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार जीविका की शुरुआत 2006 में हुई और इसकी प्रमुख गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम संगठनों का निर्माण, कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता, बैंकिंग संस्थाओं से संपर्क, महिला सशक्तीकरण, मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान से जुड़ी प्रशिक्षण प्रक्रियाएँ शामिल थीं [6]।

विश्व बैंक के अनुसार 2016 में स्वीकृत बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अर्थात जीविका II, का उद्देश्य लक्षित परिवारों की घरेलू आय में विविधीकरण और वृद्धि करना तथा पोषण और स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच और उपयोग को बेहतर बनाना था [7]। इस परियोजना के लाभार्थियों में बिहार के 300 प्रखंडों और 32 जिलों के लगभग 5 मिलियन गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाएँ शामिल थीं, और कम-से-कम 60% लाभार्थियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे वंचित समुदायों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था [7]।

इस दृष्टि से जीविका केवल ऋण-वितरण कार्यक्रम नहीं था; यह ग्रामीण सामाजिक पूँजी निर्माण का कार्यक्रम था। गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उनकी बचत, आंतरिक ऋण, बैंक-लिंकेज, प्रशिक्षण, सामूहिक निर्णय और सरकारी योजनाओं तक पहुँच को संस्थागत रूप दिया गया। गरीबी उन्मूलन के अर्थशास्त्र में यह मॉडल महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह बाजार, राज्य और समुदाय के बीच एक मध्यवर्ती संस्थागत ढाँचा निर्मित करता है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

6. उपलब्धियाँ: वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक पूँजी

जीविका की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं को समूह-आधारित वित्तीय प्रणाली से जोड़ना रही। 3ie के प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि परियोजना ने स्वयं सहायता समूह सदस्यता और समूहों के माध्यम से ऋण-प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की, साथ ही अनौपचारिक ऋण-स्रोतों पर निर्भरता और औसत अनौपचारिक ब्याज दरों में कमी देखी गई [6]। यह निष्कर्ष ग्रामीण बिहार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब परिवार अक्सर साहूकारों या अनौपचारिक ऋणदाताओं से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेते रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक भूमिका तीन स्तरों पर दिखाई देती है। पहला, वे बचत की नियमित आदत विकसित करते हैं। दूसरा, वे आंतरिक ऋण के माध्यम से आकस्मिक खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और छोटे व्यवसायों की जरूरतें पूरी करते हैं। तीसरा, वे बैंकिंग प्रणाली के साथ गरीब परिवारों का भरोसा और लेन-देन इतिहास बनाते हैं। विश्व बैंक के विवरण में भी जीविका को महिलाओं को संगठित कर वित्त, बाजार और उद्यम-विस्तार से जोड़ने वाला कार्यक्रम बताया गया है [8]।

तालिका 2: जीविका कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियाँ और गरीबी उन्मूलन से संबंध

उपलब्धि	प्रत्यक्ष प्रभाव	गरीबी उन्मूलन से संबंध
स्वयं सहायता समूहों का विस्तार	महिलाओं की सामूहिकता और बचत	सामाजिक पूँजी और वित्तीय अनुशासन
कम लागत वाले ऋण तक पहुँच	साहूकारी ऋण पर निर्भरता में कमी	ब्याज-भार में कमी
बैंक-लिंकेज	औपचारिक वित्तीय समावेशन	ऋण-इतिहास और वित्तीय पहचान
महिला नेतृत्व	निर्णय-क्षमता और सार्वजनिक भागीदारी	सामाजिक सशक्तीकरण
आजीविका प्रशिक्षण	कृषि, पशुपालन, सूक्ष्म उद्यम	आय-विविधीकरण
पोषण और स्वच्छता संपर्क	जीवन-स्तर सुधार	बहुआयामी गरीबी में कमी

विश्व बैंक ने जीविका को अन्य राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए भी महत्त्वपूर्ण क्रियान्वयन मंच माना है। विश्व बैंक के अनुसार जीविका को राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना में भी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जोड़ा गया और जीविका से प्राप्त अनुभवों को अन्य राज्यों में दोहराने योग्य माना गया [3]। इससे स्पष्ट है कि कार्यक्रम का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के संस्थागत मॉडल के रूप में भी महत्त्वपूर्ण बना।

7. सांख्यिकीय विश्लेषण: गरीबी में कमी और कार्यक्रमीय योगदान

गरीबी में कमी को किसी एक कार्यक्रम का प्रत्यक्ष परिणाम मानना सावधानी की माँग करता है, क्योंकि इस अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाएँ भी सक्रिय थीं। फिर भी जीविका जैसे कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन, महिला संगठनीकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत कर बहुआयामी गरीबी कमी की प्रक्रिया को समर्थन दिया।

© Copyright @ Authors

तालिका 3: बिहार में बहुआयामी गरीबी कमी का सांख्यिकीय आकलन

संकेतक	मान
2015–16 में बिहार का गरीबी अनुपात	51.89%
2019–21 में बिहार का गरीबी अनुपात	33.76%
कुल कमी	18.13 प्रतिशत-बिंदु
सापेक्ष कमी	34.94%
अनुमानित वार्षिक औसत प्रतिशत-बिंदु कमी	3.63 प्रतिशत-बिंदु
2013–14 से 2022–23 तक बिहार में गरीबी से बाहर आए लोग	3.77 करोड़

वार्षिक औसत प्रतिशत-बिंदु कमी की गणना 5 वर्षीय अंतराल के आधार पर की गई है:

$$\frac{18.13}{5} = 3.63$$

इसका अर्थ है कि 2015–16 से 2019–21 के बीच बिहार में बहुआयामी गरीबी अनुपात औसतन लगभग 3.63 प्रतिशत-बिंदु प्रति वर्ष कम हुआ। नीति आयोग के 2024 विवरण में बिहार से 3.77 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर आने का उल्लेख इस व्यापक परिवर्तन को और पुष्ट करता है [4]।

तालिका 4: गरीबी कमी का तुलनात्मक सूचकांक

क्षेत्र	प्रारंभिक गरीबी	अंतिम गरीबी	गरीबी कमी सूचकांक
भारत ग्रामीण	32.59	19.28	40.84
भारत शहरी	8.65	5.27	39.08
बिहार	51.89	33.76	34.94

यहाँ गरीबी कमी सूचकांक सापेक्ष कमी को दर्शाता है। बिहार की प्रतिशत-बिंदु कमी भारत ग्रामीण की तुलना में अधिक है, परंतु सापेक्ष कमी थोड़ी कम है क्योंकि बिहार का प्रारंभिक गरीबी स्तर बहुत ऊँचा था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार में गरीबी कमी का परिमाण बड़ा है, लेकिन गरीबी का शेष आधार भी उतना ही बड़ा है।

8. सीमाएँ: आय-वृद्धि और आजीविका स्थिरता की समस्या

जीविका की उपलब्धियों के साथ इसकी सीमाओं को समझना भी आवश्यक है। 3ie के अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि परियोजना के शुरुआती वर्षों में स्वयं सहायता समूह सदस्यता, समूह-ऋण और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी जैसे सकारात्मक परिणाम मिले, लेकिन उपभोग व्यय पर स्पष्ट प्रभाव नहीं पाया गया [6]। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक और वित्तीय समावेशन तुरंत स्थायी आय-वृद्धि में बदल जाए, यह आवश्यक नहीं है।

ग्रामीण बिहार में गरीबी की गहराई केवल ऋण-अभाव से उत्पन्न नहीं होती। भूमि-हीनता, बटाईदार कृषि, निम्न उत्पादकता, बाढ़-संवेदनशीलता, पलायन, स्थानीय बाजारों की कमजोरी, कौशल की कमी

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

और महिला श्रम की सामाजिक अदृश्यता भी गरीबी को बनाए रखती है। यदि स्वयं सहायता समूह केवल छोटे उपभोग ऋण या आपातकालीन ऋण तक सीमित रह जाएँ, तो उनका गरीबी-उन्मूलन प्रभाव सीमित रह सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि समूहों को उत्पादक पूँजी, मूल्य-श्रृंखला, विपणन, प्रसंस्करण और उद्यम-प्रबंधन से जोड़ा जाए।

दूसरी सीमा क्षेत्रीय असमानता है। बिहार के सभी जिलों में सामाजिक संरचना, कृषि-संरचना, बाढ़ और सूखा जोखिम, बाजार संपर्क, शिक्षा स्तर और बैंकिंग पहुँच समान नहीं है। इसलिए एक ही कार्यक्रमीय मॉडल सभी क्षेत्रों में समान परिणाम नहीं दे सकता। सीमांचल, कोसी, उत्तर बिहार के बाढ़-प्रभावित क्षेत्र और दक्षिण बिहार के अपेक्षाकृत सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी की प्रकृति अलग-अलग है। इस कारण कार्यक्रम का जिला-विशिष्ट और प्रखंड-विशिष्ट रूपांतरण आवश्यक है।

9. चुनौतियाँ: संस्थागत क्षमता, बाजार-संपर्क और सामाजिक समावेशन

विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों की सफलता का एक बड़ा आधार सामुदायिक संस्थाओं की गुणवत्ता है। यदि स्वयं सहायता समूह नियमित बैठक, पारदर्शी लेखा, ऋण अनुशासन और सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को बनाए रखते हैं, तो वे गरीबी उन्मूलन के प्रभावी माध्यम बनते हैं। परंतु कई स्थानों पर समूहों की सक्रियता, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, बैंक शाखाओं की संवेदनशीलता और स्थानीय नेतृत्व की क्षमता में अंतर देखा जाता है। विश्व बैंक ने भी जीविका के लिए पेशेवर मानव संसाधन संरचना और तकनीकी सहायता को महत्त्वपूर्ण बताया है [3]।

दूसरी बड़ी चुनौती बाजार-संपर्क है। ग्रामीण महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना पहला चरण है; उत्पाद बेचने की क्षमता, कीमत प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, डिजिटल भुगतान, ब्रांडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण इसके बाद के चरण हैं। यदि इन चरणों को मजबूत नहीं किया गया, तो आजीविका गतिविधियाँ छोटे स्तर पर अटक सकती हैं।

तीसरी चुनौती सामाजिक समावेशन की है। जीविका II में कम-से-कम 60% लाभार्थियों को वंचित समुदायों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था [7]। यह लक्ष्य सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार में सबसे गरीब, भूमिहीन, विधवा, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी महिलाओं तक कार्यक्रम की वास्तविक पहुँच सुनिश्चित करना कठिन कार्य है। अत्यंत गरीब परिवारों के पास कभी-कभी नियमित बचत की क्षमता भी नहीं होती, इसलिए उनके लिए अलग प्रकार की अनुदान-सहायता, पोषण-सुरक्षा और आजीविका-हैंडहोल्डिंग की जरूरत होती है।

10. चर्चा

ग्रामीण बिहार में विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों की भूमिका को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। पहले स्तर पर यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन का माध्यम बना। गरीब महिलाओं को बचत और ऋण की औपचारिक व्यवस्था मिली। दूसरे स्तर पर इसने सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ाया। महिलाएँ समूहों में बैठने, निर्णय लेने, बैंक जाने और सरकारी योजनाओं से संपर्क स्थापित करने लगीं। तीसरे स्तर पर इसने ग्रामीण आजीविका को नई दिशा दी। पशुपालन, कृषि-सहायक गतिविधियाँ, छोटे उद्यम और सामुदायिक व्यवसाय इसके माध्यम से आगे बढ़े।

परंतु गरीबी उन्मूलन की अंतिम कसौटी स्थायी आय-वृद्धि, जोखिम में कमी और जीवन-स्तर सुधार है। उपलब्ध साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि जीविका ने गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को गति दी, लेकिन यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। बहुआयामी गरीबी में बिहार की उल्लेखनीय कमी के बावजूद राज्य का गरीबी स्तर राष्ट्रीय तुलना में अधिक बना रहा [5]। इसलिए कार्यक्रम को अब दूसरे चरण के सुधारों की जरूरत है—समूह से उद्यम तक, ऋण से निवेश तक, बचत से उत्पादक परिसंपत्ति तक और सामाजिक सशक्तीकरण से बाजार-सशक्तीकरण तक।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

11. निष्कर्ष और सुझाव

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विश्व बैंक समर्थित जीविका कार्यक्रम ने ग्रामीण बिहार में गरीबी उन्मूलन की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने महिलाओं को सामूहिक रूप से संगठित किया, औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में मदद की और सामाजिक सशक्तीकरण का आधार तैयार किया। बिहार में बहुआयामी गरीबी 2015–16 के 51.89% से घटकर 2019–21 में 33.76% हुई, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है [5]। राष्ट्रीय स्तर पर 2013–14 से 2022–23 तक बिहार में 3.77 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर आने का उल्लेख भी इस परिवर्तन को रेखांकित करता है [4]।

फिर भी यह कहना उचित होगा कि गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया अभी अधूरी है। कार्यक्रमों को अब आय-सृजन और बाजार-संबद्ध उद्यमिता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों को किसान उत्पादक संगठनों, ग्रामीण प्रसंस्करण इकाइयों, डिजिटल वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स, स्थानीय मूल्य-श्रृंखलाओं और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। अत्यंत गरीब परिवारों के लिए केवल ऋण पर्याप्त नहीं है; उनके लिए परिसंपत्ति-सहायता, पोषण सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और दीर्घकालिक परामर्श आवश्यक है। पंचायत-स्तर पर गरीबी मानचित्रण और जिला-विशिष्ट आजीविका योजना तैयार की जानी चाहिए। बैंकिंग संस्थाओं को भी समूहों और महिला उद्यमियों के प्रति अधिक लचीला और संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

अंततः, विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने गरीबी उन्मूलन को केवल सरकारी अनुदान की प्रक्रिया न मानकर सामुदायिक संस्थागत निर्माण, महिला नेतृत्व और स्थानीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की प्रक्रिया बनाया। ग्रामीण बिहार में गरीबी उन्मूलन की आगामी रणनीति इसी आधार को अधिक उत्पादक, समावेशी और बाजार-सक्षम बनाकर आगे बढ़ा सकती है।

संदर्भ

1. नीति आयोग. (2025). *बिहार राज्य का व्यापक आर्थिक एवं राजकोषीय परिदृश्य.* नई दिल्ली: नीति आयोग, भारत सरकार।
2. बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी. *जीविका: गरीबी उन्मूलन हेतु बिहार सरकार की एक पहल.* पटना: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार।
3. विश्व बैंक. (2020). *बिहार राज्य में ग्रामीण विकास हेतु महिला समूहों की शक्ति का विस्तार.* वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
4. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार. (2024). *पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले.* नई दिल्ली: नीति आयोग, भारत सरकार।
5. यूएनडीपी इंडिया एवं नीति आयोग. (2023). *राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: प्रगति समीक्षा 2023.* नई दिल्ली: यूएनडीपी इंडिया एवं नीति आयोग।
6. हॉफमैन, वी., राव, वी., दत्ता, यू., सन्याल, पी., सुरेन्द्र, वी., एवं मजूमदार, एस. (2018). *भारत में बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के गरीबी एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रभाव.* 3आईई प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट संख्या 71. नई दिल्ली: इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन।
7. विश्व बैंक. (2016). *भारत—बिहार परिवर्तनकारी विकास परियोजना "जीविका-II".* ऋण एवं क्रेडिट विवरण. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
8. विश्व बैंक. (2017). *भारत के ग्रामीण बिहार में 7 मिलियन महिलाएँ परिवर्तन का नेतृत्व कैसे कर रही हैं.* वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।

© Copyright @ Authors

9. विश्व बैंक. *सशक्तीकरण का मापन: ग्रामीण बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने में जीविका की सफलता.* वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
10. विश्व बैंक. *भारत—बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना "जीविका": कार्यान्वयन स्थिति एवं परिणाम रिपोर्ट.* वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
11. भारत सरकार, बिहार सरकार एवं विश्व बैंक. (2012). *बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के विस्तार हेतु अतिरिक्त ऋण समझौता.* प्रेस विज्ञप्ति. नई दिल्ली/पटना/वाशिंगटन, डी.सी.: भारत सरकार, बिहार सरकार एवं विश्व बैंक।
12. विश्व्व बैंक. (2005). *बिहार: विकास रणनीति की ओर.* वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।

© Copyright @ Authors